



*(Signature)*

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 257]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 6, 1992/ज्येष्ठ 16, 1914

No. 257]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 6, 1992/JYAISTHA 16, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह जलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)  
(बैंकिंग प्रभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 1992

सा.का.नि. 585(अ).—केन्द्रीय सरकार, विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार संबंधी अपराध विचारण) अध्यादेश, 1992 की धारा 14 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार संबंधी अपराध विचारण) नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जानकारी के स्रोत :—विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार संबंधी अपराध विचारण) अध्यादेश, 1992 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् अध्यादेश कहा गया है) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अभिरक्षक, निम्नलिखित द्वारा लिखित रूप में अपने को व्यक्तिगत

रूप से दी गई या एक द्वारा भेजी गई किसी जानकारी या शिकायत को विचार के लिए ग्रहण कर सकेगा, अर्थात् :—

- (क) भारतीय रिजर्व बैंक ;
- (ख) किसी बैंक या वित्तीय संस्था ;
- (ग) सरकार के किसी प्रवर्तन या अख्येयण अधिकरण या विभाग ;
- (घ) सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी ;
- (ङ) किसी व्यक्ति जो व्यवहारी, अधिकर्ता या दलाल के रूप में प्रतिभूतियों के संव्यवहार में लगा हुआ है ;
- (च) किसी अन्य व्यक्ति जिसके प्रतिभूतियों में अधिकारों या हितों पर प्रभाव पड़ता है ;

परन्तु खण्ड (ङ) और खण्ड (च) में निविष्ट किसी व्यक्ति द्वारा भेजी गई जानकारी या शिकायत अभिरक्षक द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी यदि उसके साथ उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और किसी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित तथ्य-पत्र नहीं है।

(3) वे मामले जिनमें अभिरक्षक जानकारी की अस्वीकार कर सकेगा : जहाँ किसी जानकारी या शिकायत के साथ उस जानकारी या शिकायत में निविष्ट वस्तुओं की प्रतियाँ नहीं हैं, या वह स्पष्ट नहीं है या उसमें प्रेषक का नाम और पता नहीं है वहाँ ऐसी जानकारी या शिकायत को अभिरक्षक अस्वीकार कर सकेगा।

(4) प्रसिद्धि करने के लिए शर्तें :—यदि अभिरक्षक द्वारा प्राप्त तालिका जानकारी या वस्तुओं, प्रत्यावेद की धारा 3 की उपधारा (2) में निविष्ट अपराध गठित करने के लिए उसकी राय में पर्याप्त है तो वह उस उपधारा के अधीन उस व्यक्ति का नाम प्रसिद्धि करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा।

[फा.सं. 6/2/92 सत. (i)]

के.जे. रेड्डी, प्रतिरक्षित सचिव

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 1992

G.S.R. 585(E):—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Special Court (Trial of Offences Relating to Transactions in Securities) Ordinance, 1992, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

#### 1. Short title and commencement :

(1) These rules may be called the Special Court (Trial of Offences Relating to Transactions in Securities) Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Sources of information : The Custodian appointed under sub-section (1) of section 3 of the Special Court (Trial of Offences Relating to Transactions in Securities) Ordinance, 1992 (hereinafter

referred to as the Ordinance) may entertain for consideration any information or complaint in writing submitted personally or sent by post to him by—

- (a) the Reserve Bank of India;
- (b) any bank or financial institution;
- (c) any enforcement or investigating agency or department of the Government;
- (d) any officer or authority of the Government;
- (e) any person who is engaged in transactions of securities as a dealer, agent or broker;
- (f) any other person whose rights or interests in securities are affected:

Provided that the information or complaint sent by any person referred to in clauses (e) and (f) shall not be entertained by the Custodian if it is not accompanied by an affidavit signed by that person and duly verified by a Magistrate or a Notary Public.

3. Cases in which Custodian may reject information : Where an information or a complaint is not accompanied by copies of documents referred to in the information or complaint or is vague or does not contain the name and address of the sender, such information or complaint may be rejected by the Custodian.

4. Condition for making notification : If the material information or the documents received by the Custodian are sufficient in his opinion, to constitute an offence referred to in sub-section (2) of section 3 of the Ordinance, he may proceed to notify the name of the person under that sub-section.

[No. F.6/2/92 Vig.(i)]

K.J REDDY, Additional Secy.